



# **भाजपा ने कैग रिपोर्ट को लेकर<sup>1</sup> आआपा पर निशाना साधा**

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केरीवाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भ्रष्ट अरविंद केरीवाल सरकार की शराब नीति में 2,002.68 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आआपा की नीतियों से राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। इसमें अवैध रूप से दुकानें खोलने से 941.53 करोड़ का घाटा, सरेंडर किए गए लाइसेंसों की फिर से नीलामी न करने से 890 करोड़ रुपए की हानि। कोविड-19 के नाम पर जोनल लाइसेंसियों को 144 करोड़ रुपए की हूट, सुरक्षा जमा राशि ठीक से न लेने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल है। सचदेवा ने कहा कि आज न सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरा देश देख रहा है कि आपदा सरकार की शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा होती है। इसे सार्वजनिक करने का काम सरकार का है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विधानसभा में पेश कर आआपा के घोटालों को बाहर लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब मामले जारी जांच की गति तेज हो गई है जिसमें पता चला है कि मनीष सिसोदिया ने सभी रिपोर्ट को कूड़े में फेक दिया था। अब शराब घोटाले के मामले में अरविंद केरीवाल, सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया सामने आकर जवाब दें। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कैग रिपोर्ट को आज विधानसभा की पटल पर रखा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद

केजरीवाल नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाए। दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला आज पता चला।

तिवारी ने कहा कि केजरीवाल इनकम टैक्स के अधिकारी हैं लेकिन उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं और आज सारे भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी (आआपा) ने दस साल तक दिल्ली के लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार करने का काम पहले दिन से ही तय था कि सरकार बनाकर भ्रष्टाचार करेंगे। खंडेलवाल ने कहा कि शराब नीति बनाते समय केजरीवाल ने न कैबिनेट की मंजूरी ली न ही गवर्नर की। जिससे की इतना बड़ा घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा के सत्र में लगभग नौ विधायकों का सदन में न होना ये बताता है कि वे सभी आम आदमी पार्टी (आआपा) को छोड़ रहे हैं।



नई दिल्ली। विधानसभा में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण के लिए पथारने पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

# डीएमआरसी ने फेज-चार का निर्माण कार्य पूरा किया

# ठगी के मामले में पुलिस ने आरे को केरल से किया गिरफ्तार

# पी एलजी के अभिभाषण के दौरान शोर-शराबा करने पर आआपा के 21 विधायक तीन दिन के लिए निलंबित

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने चौथे चरण का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। डीएमआरसी के अनुसार तुगलकाबाद-एरेसिटी कॉरिडोर के छतरपुर मंदिर और इन्हु स्टेशन के बीच एक भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है। इन्हु स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) की सफल ब्रेकथ्रू प्रक्रिया में मंगलवार को उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आनंद मोहन बजाज, अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रमोद कुमार, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने मंगलवार सुबह इन्हु स्टेशन पर, 1475.00 मी. लंबी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया। यह कार्य 97 मीटर लंबी विशाल टीबीएम का उपयोग करके संपन्न किया गया।

अप अं  
समानां  
किया ज  
का ब्रेक  
नई सुरंग  
पर बना  
मी. और  
दिल्ली  
एक बन  
लाइन द  
गहराई  
रिंग्स ल  
व्यास 5  
इपीबीए  
तक नीव  
जिसमें  
लाइनिं  
मुंडका  
स्वचालि  
गया था

र डाउन मूवमेंट के लिए  
र गोलाकार सुरंगों का निर्मा-  
रहा है। दूसरी समानांतर सु-  
रंग 2025 में निर्धारित है। इ-  
औसतन 26.0 मीटर की गहराई  
गई है (न्यूनतम गहराई 15  
अधिकतम 36 मी.), जिससे ट्रॉ-  
ट्रो की सबसे गहरी सुरंगों में  
गई है। हौज खास स्थित मैजे-  
रों सुरंग लगभग 30 मीटर तक  
र बनी है। इस सुरंग में 104  
ए गए हैं, जिनका आंतरि-  
क 3 मीटर है। इस सुरंग का निर्मा-  
य (अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मेथड)  
का उपयोग करके किया गया  
कोकास्ट टनल रिंग्स की कंक्री-  
टी की गई है। इन टनल रिंग्स के  
में स्थापित एक पूरी तरह  
त कास्टिंग यार्ड में तैयार किया  
इसमें कंक्रीट सेगमेंट को शि-

सिस्टम के माध्यम का उपयोग किया गया। डीएमआरसी ने आगे बताया कि इसके सुरंग की बोरिंग प्रक्रिया चार दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी, जिसमें तीव्र ढलान और अध्रक तथा कठोर चट्टान जैसी विविध भूगर्भीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस कारण स्क्रू ऑगर क्षतिग्रस्त हो गया और इसे सुरंग निर्माण के दौरान बदला गया। मौजूदा वायाडक्ट और आसपास के निर्मित ढांचों के नीचे सुरंग निर्माण के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए गए। इसके अलावा पास की संरचनाओं पर उच्च संवेदनशीलता वाले उपकरण लगाए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भूमि धंसाव न हो। अब तक स्वीकृत चौथे चरण के कार्य के तहत कुल 40.109 कि.मी. भूमिगत लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर के तहत 19.343

नई दिल्ली, (हि.स.)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए लोगों को विदेश भेजने का ज्ञांसा देकर ठगी करने वाले एजेंट को केरल से गिरफ्तार किया है। आरोपित एजेंट एमबीए डिग्री धारक है और केरल में अपना कंसल्टेंसी ऑफिस चला रहा था। एजेंटों के संपर्क में आकर ठगी करने लगा। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कैनाल रोड थोट्टुकुट्टुकल केरल निवासी रूपेश पीआर के रूप में हुई है।

आईजीआई की डीसीपी ऊषा रंगनानी ने बताया कि 25 जनवरी को त्रिपुरा निवासी डिजो डेविस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। उसे

(हि.स.)। दिल्ली नगरालवार को उपराज्यपाल के नियन्त्रण में विधायक गतिरोध पैदा करने के बाद आदमी पार्टी के 21 अप्रैल 1947 के दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है कि यह निलंबन दो बाहर कर दिया। इसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आतंशी सहित गोपाल राय विधायकों को एक दिन के अंतर्वेदी अंबेडकर निलंबन के दौरान नरेबाजी बाहर कर दिया। इसमें वीर शंख अहलावत, चौधरी जुबैर मामा, विशेष रवि और जरनैल मेल हैं।

उपराज्यपाल के अपना नियन्त्रण करते ही विपक्षी आम लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि नारे लगा रहे थे। इसके बाद गुप्ता ने मार्शल बुलाकर नियन्त्रण के लिए लोक समिति को भेजा जाएगा। सीएजी रिपोर्ट के अन्य खंड भी भविष्य में सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सदन में हुए हंगामे के बाद आआपा विधायकों के निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने एलजी के अभिभाषण के दौरान बहुत ही असंवैधानिक तरीके से व्यवहार किया। सदन की गरिमा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उनका (आआपा के सदस्यों का) व्यवहार निंदनीय है। इसलिए उनका निलंबन तीन बैठकों (25, 27 और 28 फरवरी) तक वैध है। निलंबित आआपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में अंबेडकर की तस्वीर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और जय भीम के लिए नियन्त्रण के लिए लोक समिति को भेजा जाएगा।



नई दिल्ली। आंबेडकर की तस्वीर हटाने के मुद्दे को लेकर मंगलवार को विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते आम आदमी पार्टी के नेता।

# तइके एक मकान में अचानक आग लग गई

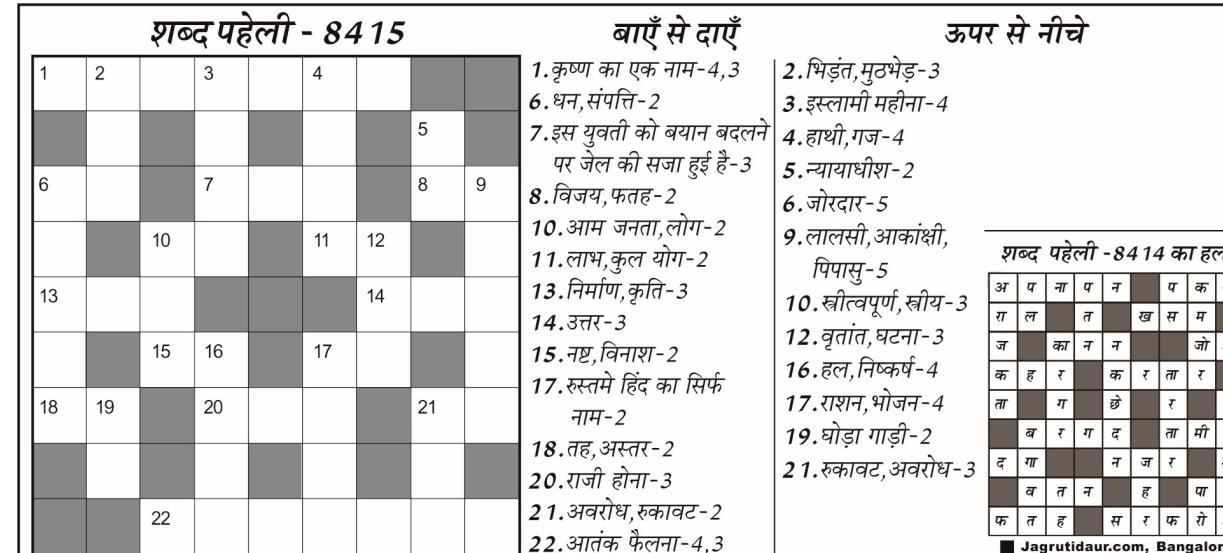
नई दिल्ली, (हि.स.)। द्वारका सेक्टर-16 इलाके में मंगलवार तड़के एक मकान में अचानक आग लग गई। घटना में दो वाहन, घरेलू सामान और वहां स्थित एक दुकान जल गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की आठ गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

दमकल विभाग के अनुसार तड़के तीन बजकर 21 मिनट पर सूचना मिली कि द्वारका सेक्टर-

16 ए आजाद नगर स्थित एक मकान में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर दमकल की आठ गाड़ियां भेजी गईं।

दमकल अधिकारी के अनुसार मकान के ग्राउंड फ्लोर पर परचून की दुकान थी। घटना में दो वाहन,

दुकान व मकान की पहली मंजिल  
जली है। दमकल अधिकारी के  
अनुसार दमकल ने दो घंटे की कड़ी  
मशक्कत के बाद आग पर काबू  
पाया। घटना में किसी के हताहत  
होने की कोई सूचना नहीं है।  
फिलहाल पुलिस आग लगने के  
कारणों की जांच कर रही है।



સ્ટૂડોકુ નવતાળ - 7353									★ ★ ★ ★ ★
મધ્યમ									
2	9		3	1				8	
3	6		2		7			9	
		7			6		2		1
	7		1						
1	3			4			7		2
					5		4		
6	2		4			9			
	5		6		9		1		8
1			5	2			6		4

			5	3		6	4	
■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरने जाने आवश्यक हैं।	3	9	7	5	1	4	6	8
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं $3 \times 3$ के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।	1	2	8	6	9	3	4	5
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।	6	4	5	2	8	7	1	3
■ पहली का केवल एक ही हल है।	5	7	3	4	6	9	2	1
	2	1	9	7	5	8	3	4
	4	8	6	3	2	1	7	9
	9	3	2	8	4	6	5	7
	7	6	1	9	3	5	8	2
	8	5	4	1	7	2	9	6



દ્વારા

# शहरों के विकास के लिए अबन मोबाइलिटी का अच्छा होना और सस्ते मकान जरूरी : खट्टर

भाषापाल, (हि.स.)। कद्रिय शहरों विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का अच्छा होना और सर्वे मकान जरूरी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। वर्ष 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50 फीसदी तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे।

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन मंगलवार को एमपी इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, पुनर्जननत्वीकरण और मध्य प्रदेश हाउसिंग रिडिवेलपमेंट पॉलिसी पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। सेशन में शामिल होने से पहले उन्होंने डिजिटल प्रोग्रेस वॉल देखी। बाग प्रिंट की डाई से कपड़े पर ब्लॉक (छापा) लगाया। अनलॉकिंग लैंड वैल्यू

इन सिटोंज विषय पर हुए सेशन में कद्राय मंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयरामगिरि, विश्वा सारंग और प्रतिमा बागरी मौजूद रहे।

कद्राय मत्रा मनाहर लाल न कहा। कि मध्य प्रदेश ने जो ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, वह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगी। स्लॉड डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जै आवास निर्माण में खासी रुचि रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ सभी को उठाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी इसको लेकर काम किया है। उन्होंने टीओडी पॉलिसी का जिक्र करते हुए

कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है। मनोहर लाल ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार के दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव का मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव

संजय शुक्ला ने अनलाइन लैड वेल्यू इसिटीज विषय पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा वि  
अफॉर्डेबल हाउसिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने  
अच्छा काम किया है। सरकार आने वाले समय  
में शहरों के विकास के लिए बॉन्ड जारी करेगी।  
इसमें ऐसे शहरों को शामिल किया जाएगा, जो  
खुद अपना बॉन्ड जारी नहीं कर सकते। आज  
जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनमें इंटीग्रेटेड  
टाउनशिप पॉलिसी शामिल है। इसको ऊरत  
अर्बन ट्रांजिशन एसिया भी कहते हैं। इसमें ऐसे  
गांवों को शामिल किया जाएगा, जो आने वाले  
समय में शहर बन सकते हैं। नगरीय विकास  
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा वि  
अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता है। वि  
2047 तक प्रदेश की जनसंख्या सात फीसद  
तक बढ़ जाएगी। प्रदेश के विकास के लिए मध्य  
प्रदेश सरकार ने दो महीने में 18 नई पॉलिस  
बनाई हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क  
बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है।



पटना। पीएमसीएच के शताब्दी वर्ष समारोह के मंच पर राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में बातचीत करते हुए।



लखनऊ। विधानसभा सत्र में जाते विधायकगण व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

**खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएँ : शिवराज सिंह चौहान**

भोपाल, (हि.स.)। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। मध्य प्रदेश निवेश के लिये आवश्यक अधोसंरचना के साथ एक लाख हैक्टेयर का लैण्ड बैंक रखने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत टमाटर, मटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, गेहूँ और चावल उत्पादन में देश अग्रणी है। उन्होंने कहा कि कृषि-उद्यानिकी उत्पादन की प्रचुर मात्रा में उत्पादन से किसान को फसल का भरपूर दाम नहीं मिल पाता है। इसलिये आवश्यक है कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाये। इससे फसलों का वैल्यू एडीशन होगा। किसान और उत्पादक इकाई, दोनों लाभान्वित होंगे। इसी तरह भारत पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग के लिये बल्ड लीडर बन सकता है। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान मंगलवार को कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसांस्करण विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में आयोजित सीड टू सेल्फ इन लार्टिंग इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटी इन एम्पी एपी फूड एण्ड डेयरी सेक्टर पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज और पौथ की नवीन किस्म विकसित करवा रहा है। देश के कृषि उत्पादन को विदेशों में बेहतर मांग मिल सके, इसके लिये भारत सरकार द्वारा चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य कर दी है। साथ ही ऑइल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी है। इसका लाभ देश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को मिलेगा। उन्होंने सभी निवेशकों

को मध्य प्रदेश में निवेश के लिये भरपूर सहयोग का आश्वासन भी दिया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने इनवेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 में आये सभी निवेशकों और विषय-विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, अपनी समृद्ध कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों ने देश में अलग पहचान बनायी है। प्रदेश के 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इसे आगामी 5 वर्षों में बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 400 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 500 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कुल जैविक उत्पादन में मध्य प्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत है। प्रदेश का रियावन लहसुन और सुंदरजा आम विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान रखता है। हमारी सरकार ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष निवेश योजनाओं को लागू करते हुए एक जिला-एक उत्पाद पहल के तहत 52 जिलों की विशिष्ट फसलों चिन्हित की हैं। राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नवीन निवेश नीतियों को निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही इन नीतियों के निर्धारण के लिये निवेशकों के सुझाव भी राज्य सरकार द्वारा आमत्रित किये गये हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिये सिंगल विणडो प्रणाली रखी गयी है, जिसमें भूमि का आवंटन एवं सभी प्रकार की अनुपत्तियां कम से कम समय में मिल सकेंगी। किसानों की आय, रोजगार, निवेश तथा नियांत में वृद्धि राज्य कृषि उत्पादन व फसल को खेत से बढ़ाव देने का उपलब्ध कराने पर नियांत उन्होंने मध्य प्रदेश में और उनके निर्यात से में राज्य के कृषि, खाद्य एवं अक्षरां पर विभिन्न विशेषज्ञों ने लिए नवाचार, तकनीकी पर रोशनी डाली। प्रसंस्करण अनुपम बेहतर माहौल तैयार करने के अंतर्गत अधोसंरचना के कृषि प्र-संस्करण निवेशकों को उत्कृष्ट ही, सिंगल विणडो प्रणाली सभी प्रकार की अनुपत्ति मिनी योजनाओं से अधोसंरचना तक के किसानों की आय, होगी। उद्यानिकी के करने के लिये भारतीय आधारित क्लस्टर व

रकार का संकल्प है।  
युक्त मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि  
पार तक पहुँचाने और उसे वाजिब दाम  
न्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है।  
ऐ, पशुपालन एवं उद्यानिकी के महत्व  
वनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम  
प्रसंस्करण एवं डेयरी क्षेत्रों में निवेश  
पापक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में  
कसानों, उद्यमियों और निवेशकों के  
प्रगति एवं संरकारी नीतियों के महत्व  
मुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य  
जन ने कहा कि प्रदेश में निवेश का  
किया जा रहा है। राज्य की सशक्ति  
त 8 फूड पार्क, 2 मेंगा फूड पार्क, 5  
नस्टर एवं एक लॉजिस्टिक पार्क  
भवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ  
ली के माध्यम से भूमि आवंटन एवं  
तेय়ाँ शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही हैं।  
लेकर उन्नत फ्रोजन लॉजिस्टिक  
ननेक कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे  
जगार एवं निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित  
ग्रंथिकास एवं वैश्विक स्तर पर वृद्धि  
रकार के सहयोग से विशेष फसल  
चयन किया गया है।

# तेईस लाख के इनामी चार नवसली सहित नौ ने किया सरेंडर

बीजापुर, (हि.स.)। जिले में लाख रुपये के इनामी चार सली सहित नौ नक्सलियों ने लवार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बीजापुर के पुलिस उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह नेही और उप अधीक्षक बीजापुर डॉ. नेन्द्र कुमार यादव के समक्ष डर कर दिया।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एलजीए बटालियन क्षेत्र में क्य आठ लाख रुपये के इनामी 5 सदस्य, एओबी डिवीजन में क्य पांच लाख के इनामी एम, जगरगुण्डा एसिया कमेटी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के लाख रुपये के इनामी दो एम कैडर के नक्सली शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों प्रेत्साहन स्वरूप 25-25 रुपये ने नगद राशि प्रदान की।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सलियों में वर्ष 2015 से सक्रिय लक्ष्मी माड़वी ऊर्फ खुटो (18), निवासी तिम्मापुर कर्कनपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, वर्ष 2013 से सक्रिय पुल्ली ईरपा ऊर्फ तारा (20), निवासी बेलमनेंडा पुजारीपारा थाना बासागुडा जिला बीजापुर, जिस पर पांच लाख रुपये का इनाम शामिल है। इन्हीं के साथ वर्ष 2011 से सक्रिय भीमे मङ्कम (24 वर्ष), निवासी मण्डीमरका वेंगुरपारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, इनाम 5 लाख, वर्ष 2008 से सक्रिय रमेश कारम (24) निवासी एड्समेटा कारममीडीपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, इनाम 5 लाख ने भी सरेंडर किया है।

इसके अलावा सरेंडर करने वालों में सिंगा माड़वी (19) निवासी पेददा धमाकरम पटेलपारा थाना पामेड़, रामलू भूषणदारी ऊर्फ रामू (27) निवासी मारूडबाका भटटीपार, देवा मङ्कम ऊर्फ मधु (32) निवासी पेदाघरमावरम पटेलपारा थाना पामेड़, रामा पूनेम ऊर्फ टक्का (30) निवासी चिन्नागेलुर नदीपारा थाना तर्रेम, हुंगा माड़वी ऊर्फ कटटी (19) निवासी धरमावरम पटेलपारा थाना पामेड़, जिला बीजापुर शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में माओवादी कैडर के छोटे-बड़े 189 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि 58 नक्सलियों के मारे जाने के 503 नक्सलियों के गिरफ्तार होने से नक्सली संगठन कमजोर होते जा रहे हैं। वहीं वर्ष 2025 में अब तक 40 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि 101 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 56 नक्सली अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं।



पाकिस्तान से आए 58 हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार, महाशिवरात्रि जगराता कार्यक्रम में लेंगे भाग

# ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੇਂ ਰਾ਷ਟ੍ਰੀਯ ਕ੃਷ਿ ਵਿਪਣਨ ਨੀਤਿ ਕਾ ਮਸੌਦਾ ਰਹ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵ ਪਾਰਿਤ

मंगलवार को राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने विधानसभा में राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति मसौदे को रद्द करने के प्रस्ताव को पेश किया। बाद में सदन में बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मसौदे का केंद्र सरकार को लिखित जवाब भेजकर कड़ा विरोध कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मसौदे को राज्य सरकार पूरी तरह से रद्द कर दिया है क्योंकि यह पूरी तरह से राज्य के हितों के खिलाफ है।

# सभा में राष्ट्रीय कृषि विपणन दा रह करने का प्रस्ताव पारित हैं, लेकिन दिल से वह और उनकी सरकार किसानों खासकर पंजाब के किसानों के साथ दुश्मनी भरा व्यवहार अपनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के कारण प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई, जबकि उन्होंने किसानों के साथ इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है क्योंकि पंजाब के किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद मजबूर होकर केंद्र सरकार को झुकाना पड़ा था।

सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार कृषि विपणन राज्य का विषय है। उस समय के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया था कि कृषि गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करती हैं और हर राज्य की स्थिति अलग होती है क्योंकि राज्य अपने फसली चक्र, विपणन ढांचे की स्थिति और स्थानीय जरूरतों को समझने की बेहतर विश्लेषण में दोते हैं। इसमें यह मनिषित होता है कि कृषि संबंधी नीतियां राज्य की आवश्यकताओं, परिस्थितियों और चुनौतियों के आधार पर बनाई जा सकें। इस नीति के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि मंडीकरण नीति किसानों के लंबे विरोध के बाद भारत सरकार द्वारा 2021 में रद्द किए गए तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को पुनः लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कृषि मंडीकरण भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार को ऐसी कोई नीति लाने के बजाय इस विषय पर आवश्यकता अनुसार उचित नीतियां बनाने के लिए यह मामला राज्य की समझ पर छोड़ देना चाहिए।

इससे पहले बहस के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जब कृषि कानून आए थे, तब उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री ने रेन्ड्र मोदी को चेतावनी दी थी कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं और उनके लिए मौत का तारंट मारित होंगे।





दिव्य भारत

**यूक्रेन पर चर्चा में मैक्रों ने ट्रंप की  
चेताया, रूस का ट्रैक रिकार्ड खराब**

वाशिंगटन, (हि.स.)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को यहां यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और कई अहम मसलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान चर्चा की। दोनों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। संबोधन में यूक्रेन में युद्ध का मुद्दा छाया रहा। मैक्रों ने कोशिश की ट्रंप अपनी महत्वाकांक्षी युद्ध रोकने की रणनीति में वास्तविक स्थिति को समझें। उन्होंने कहा कि वह शांति के समान परिणाम चाहते हैं। रूस का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। इसलिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने के प्रयास के दौरान रूस पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि मॉस्को इस बार अपने वादों को पूरा करे। उन्होंने ल्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा कि रूसी नेता से बात करने का महत्व है लेकिन केवल मजबूत स्थिति में। सीएनएन की खबर के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दृढ़ता के साथ कहा कि वह शांति चाहते हैं, लेकिन ऐसा समझौता नहीं चाहते जो कमजोर हो। साथ ही इस शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने पत्रकारों के सामने खुद को समझौते (सौदे) की तलाश में एक मास्टर बाताकार के रूप में चित्रित किया। उन्होंने ईस्ट रूम से कहा, उनकी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है। उनकी पूरी टीम शांति के प्रयासों के लिए काम कर रही है। ट्रंप ने कहा, "मैं सौदे करता हूं। मेरा पूरा जीवन सौदेबाजी है। मैं बस इतना ही जानता हूं, सौदे हैं। और मैं जानता हूं कि कब कोई इसे बनाना चाहता है और कब नहीं।" इस दौरान ट्रंप ने आग लगने के बाद पेरिस के नोट्रो-डेम कैथेड्रल के लगभग नष्ट हो जाने के बाद उसके तेजी से पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए मैक्रों की प्रशंसा की। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों के समर्थन के बिना उसका प्रस्ताव परित हो गया है। इस प्रस्ताव में अमेरिका

ने रूस को युद्ध में आक्रामक नहीं कहा है। मैत्री ने ट्रंप को भरसक यह समझाने की कोशिश की कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध की सच्चाई को समझें। ट्रंप ने यूक्रेन में यूरोपीय सांति सेना के लिए खुलेपन की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वह इस सप्ताह ह के अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिलेगे। उन्होंने पुतिन के साथ इस विचार पर चर्चा की है और रूसी राष्ट्रपति भी इस विचार के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी कि वह एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने साफ किया कि वह पुतिन को तानाशाह नहीं कहेंगे। मैत्री ने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश की कि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति के आखिरी कार्यकाल के बाद से बदल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूक्रेन हार गया तो अमेरिका अपने प्रतिद्वंद्वी अर्थात् चीन के सामने के मजोर दिख सकता है। उल्लेखनीय है कि स्टार्मर की गुरुवार को ट्रंप से मुलाकात होनी है।



वाशगटन। यूक्रेन पर चचा म मक्का ने ट्रप का चताया, कहा-रूस का ट्रक रिकाड खराब



पाठ्यक्रम सिद्धांशु पाप क्रान्ति के शास्त्र स्वतंत्र होने का लगाए जट पाठ्यक्रम स्वयंपाक न का गड़ प्राचीनता

मारताय सना क ६ पूर्व  
प्रमुख काठमांडू पहुंचे  
काठमांडू ( हिस ) | नेपाली

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाली सेना के निर्मंत्रण पर भारतीय सेना के 6 पूर्व सेना प्रमुख योगीश्वराचार्य और नेपाली सेना के 262 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को नेपाल पहुंचे हैं।

काठमांडू, (हि.स.)। अमेरिकी आव्रजन अदालत पहले ही 3,500 नेपालियों के निवासिन का आदेश देचुकी है और जिनमें से लगभग 1,500 नागरिकों को नेपाली नागरिकों को टेंपररी प्रोटेक्शन स्टेट्स

भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, जनरल दीपक कपूर, जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह, जनरल दलवीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जनरल मनोज पांडे नेपाल सेना के निमंत्रण पर नेपाल आए हैं। नेपाली सेना के अनुसार काठमांडू पहुंचे भारत के पूर्व सेना के प्रमुख नेपाली सेना के मुख्यालय में होने वाले आर्मी कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लेंगे। उक्त कॉन्क्लेव में दोनों देशों के बीच संबंधों को नागरिक स्तर पर लाने के लिए क्या काम करने की जरूरत पर चर्चा होगी।

नेपाली नागरिकों का टपररा प्राइटरान स्टेट्स (टीपीएस) का दर्जा हासिल था। अब अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अपने ताजा आदेश में टीपीएस को रद्द कर दिया है। अमेरिका में रह रहे नेपाली सेनाओं के टीपीएस धारकों की समय सीमा 24 जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद वे सभी अवैध अप्रवासी घोषित हो जाएंगे और उन्हें हर हाल में स्वदेश लौटना होगा।

अब तक टीपीएस वाहकों को पूरे अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल रही थी, जिसे अब रद्द करने का फैसला किया गया है। अमेरिका के टेंपररी प्रोटेक्शन स्टेट्स (टीपीएस) को रद्द करने से यह सुविधा पाने वाले 17 देशों के करीब 8 लाख 50 हजार प्रवासी अवैध घोषित हो जाएंगे। ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले से उन अप्रवासियों को या तो स्वयं घर लौटना होगा या अमेरिका उनके साथ अवैध अप्रवासियों की तरह व्यवहार करेगा और उन्हें घर वापस जाने के लिए मजबूर करेगा।

टीपीएस धारकों को हर साल अमेरिकी आव्रजन

**अमेरिका में नेपाल के टोपौएस धारकों को समय सीमा 24 जून तक, अवैध अप्रवासी घोषित होंगे**

काठमाडू, (ह.स.) | अमरिका आव्रजन अदलत  
पहले ही 3,500 नेपालियों के निर्वासन का आदेश देते  
चुकी है और जिनमें से लगभग 1,500 नागरिकों को  
नेपाली नागरिकों को टेंपररी प्रोटेक्शन स्टेट्स  
(टीपीएस) का दर्जा हासिल था। अब अमेरिकी  
होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अपने ताजा आदेश में  
टीपीएस को रद्द कर दिया है। अमेरिका में रह रहे नेपालि  
के टीपीएस धारकों की समय सीमा 24 जून को समाप्त  
हो रही है। इसके बाद वे सभी अवैध अप्रवासी घोषित  
हो जाएंगे और उन्हें हर हाल में स्वदेश लौटना होगा।  
  
अब तक टीपीएस वाहकों को पूरे अमेरिका में काम  
करने की अनुमति मिल रही थी, जिसे अब रद्द करने  
का फैसला किया गया है। अमेरिका के टेंपररी प्रोटेक्शन  
स्टेट्स (टीपीएस) को रद्द करने से यह सुविधा पाने  
वाले 17 देशों के करीब 8 लाख 50 हजार प्रवासी  
अवैध घोषित हो जाएंगे। ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले  
से उन अप्रवासियों को या तो स्वयं घर लौटना होगा  
या अमेरिका उनके साथ अवैध अप्रवासियों की तरह  
व्यवहार करेगा और उन्हें घर वापस जाने के लिए  
मजबूर करेगा।

विभाग के साथ फिर से पजाकृत करना हाता था लेकिन अब अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने टीपीएस धारकों के नए पंजीकरण या उसके दोबारा नवीकरण की प्रक्रिया भी बंद कर दी है।

इसी तरह सीरिया से 3800, कैमरून से 3200 निकारागुआ से 2900, बर्मा से 2300, यमन से 1800, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान, इथियोपिया आदि से आए अप्रवासियों ने भी टीपीएस सुविधा लंबे है। इनको अमेरिका के विभिन्न राज्यों में लाकर बसाया गया था, जिनमें सर्वाधिक फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क तथा कैलिफोर्निया में हैं। राष्ट्रीय आव्रजन फर्म वे अनुसार अमेरिका में 3 लाख 50 हजार वेनेजुएला के नागरिक टीपीएस वाहक हैं। उनकी मान्यता इसके वर्ष अप्रैल तक ही है। इसी तरह होंडुरास के टीपीएस वाहकों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। होंडुरास वे 54 हजार लोगों ने टीपीएस लिया है, जबकि चौथे स्थान यूक्रेन का है। यूक्रेन में लगभग 50 हजार लोगों ने अब तक टीपीएस लिया है। अफगानिस्तान पांचवें स्थान पर है। यहां के करीब 8,200 लोगों को टीपीएस सुविधा मिल चुकी है, जबकि नेपाल यह सुविधा पांच में छठे स्थान पर है।

संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार, नेपाल और भूटान ने यूक्रेन के पक्ष में डाला वोट, भारत और चीन अनुपस्थित रहे

काठमांडू, (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पड़ोसी देश स्थांमार, नेपाल और भूटान ने भी यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया है। भारत और चीन इस मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान कुल 93 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका ने यूक्रेन के विरोध में पहली बार मतदान करके रूस के साथ चल रही वार्ता को और आगे पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान कुल 93 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, सिंगापुर सहित लगभग सभी यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश स्थांमार, नेपाल और भूटान ने भी यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया है।

बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के तीसरे साल संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में एक प्रस्ताव लाया गया। मंगलवार को हुए मतदान के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के विरोध में मतदान करके रूस और यूक्रेन को लेकर अपनी पुरानी नीति में बदलाव का स्पष्ट संदेश दे दिया है। इससे पहले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में ही मतदान किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस पहल से यूक्रेन के राष्ट्रपति जिलेंस्की मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, ईराक, ओमान, सहित कई खाड़ी देश और इस्लामिक देश शामिल हैं। अमेरिका के पाला बदलने के बाद कुछ देशों ने इसका विरोध करने के बजाए मतदान में अनुपस्थित रहना बेहतर समझा है। यूक्रेन के विपक्ष में मतदान करने वाले देशों की संख्या सिर्फ 18 ही है। इनमें अमेरिका के अलावा, रूस, इजरायल, हंगरी, उत्तर कोरिया, बेलारूस जैसे देश शामिल हैं।



**सियोल / दक्षिण कोरिया में निमाणीधीन पल छहा, तीन की सौत, सात घायल**

# कीलों और पत्रकारों खेलाफ मोर्चा खोला

इस्लामाबाद, (हि.स.)। अस्वीकार कर दिया। इसे सविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना। यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि पेका (संशोधन) अधिनियम, 2025, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित मीडिया कर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार को याद दिलाया गया है कि इस संधि पर पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह संशोधन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। बैठक में मौजूद पत्रकारों और वकीलों ने पेका (संशोधन) अधिनियम, 2025 की निंदा करते हुए इसे इसके अध्यक्ष मियां मोहम्मद रुफ़ाउत्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद इशाक नोटर्जई, बलूचिस्तान के उपाध्यक्ष मोहम्मद औरंगजेब खान, कार्यवाहक सचिव चौधरी तनवीर अख्तर, वित्त सचिव मुनीर अहमद मलिक, आयशा मलिक, हमूद उर रहमान अवान, बलूचिस्तान बार काउसिल के सदस्य खलील पानेजई और हाफिज अहसान खोखर ने हिस्सा लिया। मीडिया की ओर से बैठक में मुनीजा जहांगीर, अरशद अंसारी, अफजल बट, जाहिद हसन, हामिद मीर, मजहर अब्बास, आरिफा नूर और अन्य शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि सिंध हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (पेका) में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती दी गई है।

# नतन्याहू के बयान से सौरिया में उबाल, दारा गवनरीट के कई शहरों में प्रदर्शन

दामशक, (ए.स.प.)। इजराइल के प्रधानमंत्रा बेंजिमिन नेतन्याहू के बयान से सीरिया के लोग गुस्से में हैं। दक्षिणी सीरिया के दारा गवनरेट के कई शहरों और कस्बों में सोमवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उत्तर आए और प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि दक्षिणी सीरिया को विसैन्यीकृत क्षेत्र घोषित जाए। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के बयानों की निंदा करते हुए उनके खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेतन्याहू को सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अरबी न्यूज वेबसाइट 963+ की खबर के अनुसार, दारा के एक शहर के शूरा काउंसिल के प्रमुख इमाद अल-बातीन ने कहा कि नेतन्याहू के बयान सीरियाई संप्रभुता के उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी सीरिया के लोग नेतन्याहू की थोपी गई किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। नई सीरियाई सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए। दारा मीडिया सिंडिकेट के प्रमुख उमर अल-मसरी ने कहा कि नेतन्याहू ऐसे बयान देकर उकसावे की राजनीति कर देश की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं।

दारा बार एसोसिएशन के प्रमुख सुलेमान अल-

करफान न कहा कि किसा भा बाहरा दश का संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू के इस रुख के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है। इजराइल की विस्तारवादी योजना का डटकर मुकाबला किया जाएगा। सीरिया में यह गुस्सा नेतन्याहू के दो दिन पहले जारी बयान को लेकर है। उन्होंने कहा था कि सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी नई सीरियाई सेना या विद्रोही समूहों को घुसने नहीं दिया जाएगा। इजराइल की सेना अनिश्चितकाल तक दक्षिणी सीरिया के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेगी। उन्होंने साफ किया था कि इजराइल हयात तहरीर अल-शाम जैसे विद्रोही समूहों को भी दक्षिणी सीरिया में घुसने नहीं देगा।

इस बीच तहरीर अल-शाम के नेता अल-शरा ने सीरियाई राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन में कहा कि सीरियाई क्षेत्रों की एकता और देश को विभाजित करने वाली किसी भी योजना को वह स्वीकार नहीं करेंगे। हथियारों को राज्य तक सीमित रखना उनका कर्तव्य और दायित्व है। अल-शरा ने कहा कि नागरिकों को आज सीरिया के पुनर्निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा है।

## दक्षिण कोरिया में निमाणीधीन पुल ढहा, तीन की मौत. सात घायल

सियोल, (हि.स.)। दक्षिण कोरिया में मंगलवार सुबह लगभग 9:49 बजे एक निमाणीधीन पुल ढह गया। यह हादसा चुंगचे ओंग प्रांत के चेओनान के पास सियोल-सेजोंग राजमार्ग पर हुआ। हादसे में कम से कम तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। द कोरिया टाइम्स के अनुसार, सियोल-सेजोंग राजमार्ग पर निर्माण के दौरान पुल के लिए तैयार किए गए 50 मीटर लंबे पांच स्टील सपोर्ट ढह गए। गंभीर रूप से घायल सात लोगों में से एक को कार्डियक अरेस्ट हुआ। अग्निशमन अधिकारियों का मानना है कि कई कर्मचारी मलबे में ढबे हुए हैं। राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने आंतरिक और सुरक्षा मंत्रालय, भूमि, बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी, राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और दृष्टिक्षण चुंगचे ओंग प्रांतीय सरकार को तेजी के साथ राहत और बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इस पुल का निर्माण हुँडई इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सकुशल बाहर निकालने की है।



